जांच समिति की रिपोर्ट से और गहरा हुआ बोर्ड पर लगा दाग

बिके हुए जजों ने क्रिकेट बोर्ड के चोरों का शाह ठहराया

फ़जल इमाम मल्लिक

क्या मजाल जो क्रिकेट की खामियों को लेकर कोई नेता कुछ बोलता हो। क्रिकेट के खेल में नरेंद्र मोदी, फारूख अब्दुल्ला, अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार सब एक जैसे ही नज़र आते हैं। क्रिकेट के भ्रष्टाचार पर कोई कुछ नहीं बोलता, न ही यहां 'काले धन' की कोई चर्चा की जाती है। मामला साफ़ है। खुद भी खेलो और दूसरों को भी खेलने दो। इकबाल के शब्दों में कहा जाए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मामला 'एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदानवाज' जैसा ही दिखता है।

नई दिल्ली, 28 जुलाई। स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने जांच की जिम्मेदारी जिन दो पूर्व न्यायाधीशों को सौंपी थी, उनकी रविवार को सौंपी रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए हैं उससे देश के क्रिकेट प्रेमियों को कोई बहुत ज़्यादा हैरत हुई है, ऐसा लगता नहीं है। अपना गला फंसता देख कर आननफानन में जिस तरह से बिना किसी से राय-मश्विरा किए श्रीनिवासन ने अपने ही प्रदेश के जिन दो पूर्व न्यायाधीशों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी दिन साफ हो गया था कि बोर्ड की बनाई इस कमेटी की रिपोर्ट कुछ इसी तरह की आयेगी। पूर्व न्यायाधीश टी जयराम चौटा और आर बालासुब्रहमण्यम की दो सदस्यीय समिति ने कोलकाता में बीसीसीआई कार्यकारिणी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मेयप्पन, राजस्थान रायल्स के मालिक राज कुंद्र और इंडियन सीमेंट्स की भूमिका को खारिज करते हुए उन्हें पाक-साफ बताया गया है। काफ़ी शोर-शराबे के बाद अध्यक्ष के कामकाज से खुद को अलग रखने वाले श्रीनिवासन के लिये इसी के साथ अध्यक्ष पद पर वापसी का रास्ता साफ़ हो गया है। श्रीनिवासन ने काफ़ी दबाव के बाद स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिये तीन सदस्यीय पैनल गठित किया था जिसमें दो जजों के अलावा बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव संजय जगदाले शामिल थे। तब श्री निवासन ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन दो जून को वे जांच चलने तक कामकाज से अलग रहने को तैयार हो गए थे। उन्होंने यह कदम भी जगदाले और तत्कालीन कोषाध्यक्ष अजय शिर्के के त्यागपत्र के बाद उठाया था जिन्होंने श्रीनिवासन से नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा मांगा था। जगदाले के इस्तीफ़े के बाद समिति में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं किए जाने की वजह से भी समिति को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन बोर्ड करता वही है, जो उसे पसंद है। जांच को लेकर भी उसने ऐसा ही रवैया अपनाया था।

लेकिन इस रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कामकाज के तरीके पर फिर से न सिर्फ सवाल खड़ा किया है बल्कि चेहरे पर लगे दाग को और भी गहरा किया है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट को लेकर अभी बहुत कुछ कहा सुना जाएगा क्योंकि जांच समिति को आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में उनकी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। जबकि मेयप्पन से लेकर कुंद्रा तक ने सट्टेबाजी में शामिल होने की बात किसी न किसी तौर पर कबूली थी। लेकिन जांच समिति को कहीं कुछ नहीं मिला। इसी के साथ सब कुछ साफ़ हो गया-क्रिकेट भी, अधिकारी भी, टीमें भी। यानी पैसा बनाने की एक तरह से छूट मिल गई।

क्रिकेट में 'लेनदेनल' का जो काला खेल चल रहा है, समिति की रिपोर्ट ने उसे एक तरह से सफेद करार कर भविष्य की राह भी तय कर दी है। यह भी तय हो गया है कि क्रिकेट में उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जिनका दबदबा है, राजनीतिक रसूख है और बड़ी हैसियत है। वे देश में क्रिकेट को अपने तरीके से चलाते रहेंगे। सच तो यह भी है कि क्रिकेट के इस काले खेल में हर कोई शामिल है। सियासी दल संसद में भले अलग-अलग सुर में बोलें, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर सब एक ही सुर में बोलते-बतियाते हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस सब एक ही रंग में रंगे होते हैं क्या मजाल जो क्रिकेट की खामियों को लेकर कोई नेता कुछ बोलता हो। क्रिकेट के खेल में नरेंद्र मोदी, फारूख अब्दुल्ला, अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार सब एक जैसे ही नज़र आते हैं।

क्रिकेट के भ्रष्टाचार पर कोई कुछ नहीं बोलता, न ही यहां 'काले धन' की कोई चर्चा की जाती है। मामला साफ़ है। खुद भी खेलो और दूसरों को भी खेलने दो। इकबाल के शब्दों में कहा जाए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मामला 'एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदानवाज' जैसा ही दिखता है। इसलिये स्पॉट फिक्सिंग का मामला उजागर होने के बाद क्रिकेट से जुड़े किसी बड़े नेता ने न तब कुछ कहा था और न ही अब कुछ कह रहे हैं। क्रिकेट की राजनीति देश की राजनीति से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जहां हर किसी को अपनी मर्जी से गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण का मौका मिल रहा है। इसलिये सब चुप हैं, सब देख रहे हैं और मान कर चल रहे हैं कि देर-सवेर उनकी बारी भी आएगी।

बोर्ड के उपाध्यक्ष रविवार को कोलकाता में जब यह कह रहे थे कि जजों को राज कुंद्रा, इंडिया सीमेंट और राजस्थान रायल्स के खिलाफ़ किसी तरह की गड़बड़ी करने का कोई सबूत नहीं मिला है, तो समिति के कामकाज के तरीकों पर शक उठना लाजिमी है।

देश में पहली बार उजागर हुए इस तरह के मामले में जिस तरह का रवैया बीसीसीआई का रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जांच समिति ने वही कुछ किया जो श्रीनिवासन और उनके सहयोगी चाहते थे। चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ़्तार होते हैं, राज कुंद्रा सट्टेबाजी की बात कबूलते हैं, लेकिन समिति को किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिलता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बलिहारी। वह जो चाहता है वैसा ही होता है। पहले भी यह देखने को मिला था, स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्या पता कल एस श्रीनिवासन और दूसरे दागी क्रिकेटर को पाक-साफ़ होकर मैदान पर दिखाई दें क्योंकि जब अधिकारी क्रिकेट-क्रिकेट खेल सकते हैं तो खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही ठहरे।

देर-सवेर श्रीनिवासन फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाते नजर आ जाएंगे। बोर्ड के सदस्य गदगद हैं। कहीं कुछ नहीं निकला। समिति भी खुश, जिम्मेदारी से पीछा छूटा, अब बोर्ड जाने और श्रीनिवासन। लेकिन सवाल यह है कि इस रिपोर्ट से क्या बोर्ड के दाग धुल जाएंगे? लगता तो नहीं। क्योंकि इस रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेहरे पर लगे दाग को और गहरा ही किया है।

मज़दूर आवाज़

मज़दूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मज़दूर वर्ग का कार्य है

परिस्थितियों के साथ संघर्ष या समझौता

हम वैज्ञानिक युग के इंसान हैं। और समाज में व्यक्तियों की चेतना का स्तर भिन्न हैं। समाज में व्यक्तियों को देखा जाय तो वे दो प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हैं। और दूसरा वे जो परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं। मनुष्य की चेतना समाज व्यवस्था की चेतना पर निर्भर करती है हम देखते हैं कि व्यक्ति समाज व्यवस्था की किसी बुराई के साथ दो तरह से व्यवहार करता है। एक व्यक्ति उन बुराइयों को बदलने का प्रयास करता है। जबकि दूसरा इन बुराईयों के साथ तालमेल बिठा लेता है। आज हम देखते हैं कि परिस्थितियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वालों की संख्या कम है जबकि परिस्थितियों के साथ समझौता करने वालों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि आज का समाज पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज व्यक्ति को व्यक्तिवादी बनाता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति को मैं, मेरा परिवार और मेरी सम्पत्ति की जड़ता से बांध देता है। और व्यक्ति अपना सामाजिक दायरा खत्म कर लेता है जिसके कारण उसमें संघर्ष करने का नैतिक साहस खत्म हो जाता है। वह कहता है कि 'जो चल रहा है, ठीक चल रहा है', 'कुछ नहीं बदल सकता', 'सदा से यही होता रहा है', 'मै अकेला क्या कर सकता हूं' आदि कहकर अलगाव में पड़ जाता है। परन्तु जो व्यक्ति शोषण का शिकार है और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। समाज का तर्क के आधार पर विश्लेषण करने वाले व्यक्ति भी परिस्थितियों से संघर्ष करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं।

इन दिनों तर्कों से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो व्यक्ति 'मैं' को अहमियत देते हैं, वे संघर्ष से दूर भागते हैं जो 'हम' में विश्वास रखते हैं वे संघर्ष के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। परिस्थितियों दूर भागना हमें लम्बे समय तक उन परिस्थितियों के इर्द-गिर्द घुमाता रहेगा। परिस्थितियों से संघर्ष हमें नयी सुबह का संकेत देगा। हम मज़दूर आज कम वेतन मिलने के कारण या तो ओवर टाइम के लिये तड़पते हैं वे अपना खर्च कम कर परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। जितना ओवरटाइम हमको करने के लिये मिलता है। उसको नहीं छोड़ते जिसके कारण ज़्यादा काम करने के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। और ओवर टाइम से ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर हम कम वेतन के कारण जानकर उसके साथ संघर्ष करने लग जाते हैं तो हम मज़दूरों की जिंदगी में एक नया सवेरा जरूर आता है। इसके साथ ही हम वैज्ञानिक युग में जरूर जी रहे हैं लेकिन पूंजीवादी तंत्र ने अपने प्रचार माध्यमों (सिनेमा, रेडियो, अखबार, फेसबुक, इण्टरनेट आदि के माध्यम से) से पिछड़ी मूल्य-मानताओं, नग्न संस्कृति, उपभोक्तावादी चरित्र और धार्मिक जड़ता को समाज में स्थापित कर रखी है। और वह लगातार इन चीजों का प्रचार करता है। आज वैज्ञानिक युग होने पर भी समाज में तर्कशक्ति नगण्य सी दिखाई देती है और जो तर्क चलाते हैं उनका चरित्र वैज्ञानिक नहीं होता है। इस कारण समाज में पिछड़ी मूल्य-मान्यताओं का वर्चस्व है और समाज जड़ता का शिकार है। इन सबसे आज संघर्ष करने की जरूरत बनती है। इस जड़ता को आज मज़दूर आंदोलन ही तोड़ सकता है। मज़दूर आंदोलन ही समाज में समाजवादी समाज की चेतना को स्थापित करता है। संगठित मज़दूर वर्ग की समाज के अन्य वर्गों (छात्र, किसान, महिलाओं, निम्न मध्यम वर्ग) को संगठित कर समाजवादी क्रांति कर सकता है इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम मज़दूर संगठित होकर अपने ऐतिहासिक मिशन की तरफ़ कूच करें। और एक ऐसा समाज बनायें जिसमें 'मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण' संभव ना हो। आओ साथियों! लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा है।

-योगेश, गुड़गांव

'पूंजीवाद' कैसे पनपता है

मज़दूर संगठनों के सहयोग से 1965 में चुनाव जीतने वाले श्री बसंत साठे राजनीति में सक्रिय हुए। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वचाइन कर ली। 1970 से 1995 तक कभी ऊर्जा मंत्री तो कभी प्रचार मंत्री या सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। राजनीति में रहकर उन्होंने गरीब, आम मज़दूरों का हक मारा तथा भ्रष्टाचार करके अपने पुत्र सुभाष साठे को उद्योगपति बना दिया। सुभाष साठे ने दो करोड़ रुपये की लागत से सन वैक्यूम फार्मस लिमिटेड के नाम से फैक्टरी खोली। आज वे चार फैक्टरियों के मालिक हैं। सभी फैक्टरियों का अर्न ओवर 240 करोड़ रुपये है।

सन वैक्यूम ग्रुप में जो भी मज़दूर काम कर रहा है उसकी तनख्वाह काफ़ी कम है। वह तनख्वाह से केवल भोजन कर सकता है, मकान नहीं बना सकता। वही उद्योगपति 25 साल के दौरान अरबपति बन जाता है। मज़दूर दिन-रात काम करता है, न्यूनतम वेतन पर कार्य करता रहता है वह गरीब का गरीब रह जाता है। पूंजीपति मज़दूरों का विनाश कर स्वयं अमीर बनता जाता है। जो मज़दूर 18 साल से काम कर रहा है। उसको भी केवल जीने लायक ही वेतन मिलता है। जब वह पेमेण्ट बढ़ाने की बात करता है तो पूंजीपति कहता है कि यह पलाण्ट नया है। इसलिये वेतन नहीं बढ़ सकता है। जब पुरानी फैक्टरी का मज़दूर तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। तो वह कहता है कि तुमने हमारे लिये क्या जोड़ा है। मज़दूर की मेहनत से अपना अरबपति बनना उसे दिखायी नहीं देता है।

इस तरह मज़दूरों का हक मारकर पूंजीवाद बढ़ता रहता है।

-एक मज़दूर, गुड़गांव